डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 08 फरवरी 2021, वर्ष-6, अंक-45

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

■ प्रदेश के अन्नदाताओं को सरकार मुहैया कराएगी ग्लोबल मार्केट

■ इंडोनेशिया, कुवैत, इजरायल व ईरान, तक भेजेंगे गेहूं और आलू

विदेश जाएगा हमारा गेहूं

अरविंद मिश्रा, भोपाल

देश में एक ओर भले ही एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन मप्र के किसान जल्द ही मिडिल और ईस्ट के देशों तक अपना आलू और गेहूं बेच सकेंगे। नाबार्ड की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (एआईएफ) योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के क्लस्टर बनाकर जिला प्रशासन इन्हें एक साथ लाएगा। एक्सपर्ट की मदद से अच्छी क्वालिटी का माल पैदा करने, उनके छंटाई, निकलवाई, वाशिंग और फिनिशिंग के बाद पॉलिशिंग कर एक्सपोर्ट करेगा। इसके गठन के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भी बुला लिए हैं और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजा गया है। अगले एक माह में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ऐसे होगा अमल

ड्यूरम गेहूं थोड़ा कड़ा गेहूं है, जिसका छिलका आम गेहूं से कड़क होता है। यही इस गेहूं की खूबी है। यह गेहूं मोटा दलिया बनाने में काम आता है। सेमोलिना पास्ता बनाने में काम आने वाला मुख्य तत्व है। पहली समिति जो जमीन उपलब्ध कराएगी, उसी की जमीन पर इसका प्लांट लगेगा। यह स्टोरेज सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। यही लीड समिति होगी। अन्य समितियां वाशिंग, ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकेजिंग व सेमोलिना बनाने का काम करेगी।

मीडिल ईस्ट के देश

बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल, यमन, जार्डन, कतर, कुवैत, ओमना, फिलिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस।

साऊथ ईस्ट एशिया

कंबोडिया, लाओस, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर।

मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

» खेत से प्लॉट पर ही पहुंचेगा आलू और गेहूं

» अब मुंबई में ग्रेडिंग भी निरस्त नहीं हो सकेगी

» किसान सीधे एक्सपोर्टर को बेच सकेंगे माल

» अब 25 फीसदी ज्यादा मिलेंगे उपज के दाम

» किसानों की समितियां बनाएगा जिला प्रशासन

किसानों को मिलेगा भाव

नाबार्ड के तहत एक कृषि साख समिति को दो करोड़ का लोन मिलता है, वह भी मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के बजाय इंदौर जिला प्रशासन चार-चार समितियों के क्लस्टर बना रहा है, ताकि एक साथ 8 करोड़ में एक क्षेत्र के कुछ गांवों का अपना एक सेटअप (प्लांट) बन जाए। एक किसान को अपनी फसल का सीधे 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा दाम मिलेंगे। एक क्लस्टर में 8 से 10 हजार किसान जुड़ेंगे। ऐसा अलग-अलग समितियों के साथ किया जाएगा। प्लांट लगवाने के साथ, उन्हें सेल्स और ब्रांडिंग की टीम भी दी जाएगी। सरकार की एक जिला एक प्रोडक्ट, योजना के तहत इंदौर में आलू को चुना गया है। सहायक उत्पाद में गेहूं को लिया है।

मप्र का आलू- मिडिल ईस्ट और साऊथ ईस्ट एशिया जाएगा। ड्यूरम गेहूं भी शार्टिंग, पैकेजिंग के बाद भेजा जाएगा। एक बार प्लॉट लगने और पूरी प्रक्रिया होने से हमारा कांपिटिशन सीधे टर्की से होगा। टर्की और हमारे रेट में भी अंतर होगा। टर्की की फसल हमसे देर से निकलती है। हमारे यहां मार्च अप्रैल में तो उनकी जून-जुलाई में आती है।

मनीष सिंह, कलेक्टर, इंदौर

जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ड्यूरम गेहूं होगा वह विदेशों को निर्यात होगा, जिससे वहा सेमोलिना, खुशखुश एवं हाई-ब्रान बिस्किट बनाएं जाएंगे। दूसरी ग्रेड का गेहूं डोमेस्टिक मार्केट में सेमोलिना बनाने के लिए बेचा जाएगा। समिति के प्लांट पर भी सेमोलिना बनाया जाएगा।

अभय बेड़ेकर, अपर कलेक्टर, एवं प्रोजेक्ट प्रमुख

अभी किसान अलग-अलग काम करते हैं। जब एक कंपनी बतौर काम करेंगे तो फसल पर ध्यान दे पाएंगे और सीधे एक प्लेटफार्म से अपनी फसल को विदेश तक पहुंचा सकेंगे। अभी जो उपज मुंबई जाती है, वहां भी वह कई बार ग्रेडिंग में फेल हो जाती है। जब ग्रेडिंग यहीं होगी तो एक्सपोर्ट करने में परेशानी खत्म हो जाएगी।

रूद्रा सिंग, प्रोजेक्टर कंसलटेंट, इंदौर

नर्मदे हर...जिंदगी भर...

भोपाल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां नर्मदा से विकास के लिए प्रार्थना की। नर्मदे हर-जिदंगी भर के जयकारे के साथ सभी के कल्याण और समृद्धशाली जीवन की कामना के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा सपरिवार शुरू की।

शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला

24 लाख किसानों का 550 करोड़ ब्याज माफ

संवाददाता, भोपाल

किसान आंदोलन के बीच मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। शिवराज कैबिनेट ने सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के तहत प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था। लेकिन समय पर मूल राशि नहीं चुकाने के कारण किसानों पर ब्याज का बोझ पड़ रहा था, जिसे शिवराज सरकार ने माफ कर दिया है। इससे प्रदेशभर के करीब 24 लाख किसान सीधे लाभांवित होंगे। हालांकि, इससे प्रदेश सरकार पर करीब 550 करोड़ रुपए का भार आएगा। यह राशि सरकार प्रदेश के सहकारी बैंकों को देगी। वहीं मप्र में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पकालीन कृषि ऋण मिलेगा। कैबिनेट बैठक में शून्य प्रतिशत ब्याज दर वाली योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया गया है। एक साल में 24 लाख किसानों को 14000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया है। दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14.80 करोड़ के अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। लॉकडाउन के कारण किसानों को दुग्ध संघ ने राशि का भुगतान नहीं किया था।

■ सहकारी बैंक से लिए कर्ज का ब्याज नहीं देना होगा

■ दुग्ध संघ को घाटे से उबारने 14.80 करोड़ की मंजूरी

हर ब्लॉक में होगा एक्सीलेंस स्कूल

कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन मंत्री इंदरसिंह परमार ने दिया। इस दौरान तय किया गया कि हर ब्लॉक में एक एक्सीलेंस स्कूल खोले जाएंगे। दो स्कूलों के बीच कम से कम 45 किलोमीटर की दूरी होगी। ऐसे स्कूलों की संख्या 9920 तय की गई है।

पवन ऊर्जा संयंत्रों में बनेगी सौर ऊर्जा

भोपाल। प्रदेश में जल्दी ही पवन ऊर्जा संयंत्र स्थलों पर सोलर ऊर्जा पैनल्स भी लगाए जाएंगे। इससे दिन में सौर ऊर्जा और रात में पवन ऊर्जा मिलेगी, जो मप्र को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। देश में इस वर्ष सबसे अधिक सोलर पार्क मप्र के लिए स्वीकृत हुए हैं। इनमें आगर-शाजापुर-नीमच, ओंकारेश्वर, छतरपुर और मुरैना सोलर पार्क शामिल है। सभी पार्क 2022-23 में पूर्ण हो जाएंगे। रीवा-2, छतरपुर, मुरैना, सागर और रतलाम सोलर पार्क के लिए जमीन चयनित कर ली है। सभी प्रोजेक्ट में काम जारी है।

» कृषि के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को मिलेगी मदद » संकलन विवि के 16 वैज्ञानिकों के दल ने किया

जबलपुर विवि ने बनाया खेती का कृषि एटलस

संवाददाता, भोपाल

शासकीय जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर ने मध्य प्रदेश की खेती का कृषि एटलस तैयार किया है। इसमें फसलों और कृषि से जुड़े अन्य मदों के बारे में जिलेवार जानकारी प्रदर्शित की गई है। इससे कृषि नीति निर्धारकों, उद्योगों, व्यापारियों और शोधकर्ताओं को काफी मदद मिलेगी। इस एटलस को हाल ही में जारी किया गया है। यह देश में इस तरह की पहली एटलस है और इससे लोगों को एक नजर में राज्य के कृषि क्षेत्र के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक एटलस का संकलन कृषि विभाग के डीन डॉ. धीरेंद्र खरे के नेतृत्व में विवि के 16 वैज्ञानिकों के दल ने किया है। कृषि एटलस को

दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसमें मप्र की प्रमुख अनाज फसलों के आंकड़े का विश्लेषण कर बताया गया है कि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष संभावित क्षेत्र कौन से हैं। मप्र में 2,42,14,048 हेक्टेयर में फसल उगाई जाती है। इसमें से 43.06 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है।

जिलेवार मिलेगी जानकारी

कृषि एटलस में जलवायु, फसल जलवायु, उद्यानिकी फसलें, कृषि उत्पाद निर्यात, औषधीय फसलें, वानिकी, कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, उर्वरक उपयोग, कृषि शिक्षा, अनुसंधानं, पशुपालन की जानकारी प्रदर्शित है।

इनका कहना है

प्रदेश स्तर पर कृषि एटलस की अहम जानकारी वैज्ञानिक, शिक्षण, कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के साथ ही कृषि नीति निर्धारकों और व्यापारियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, जबलपुर

ई-नाम में शामिल होंगी सभी मंडियां

भोपाल। केंद्र की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में मप्र की सभी मंडियों को शामिल करने के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। मप्र की 80 मंडियों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शेष मंडियों में भी शीघ्र ही योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। केंद्र द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कृषि विपणन में ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार में अभिनव पहल है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संचालक प्रियंका दास ने बताया कि इसमें एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल लांच कर इसे और मजबूत किया गया है।

प्रदेश के वेटलैंड्स का अब सुधरेगा स्वास्थ्य

50 तालाबों के हेल्थ-कार्ड दिल्ली भेजे गए, छत्तीसगढ़-तेलंगाना को भी मिलेगी मदद

संवाददाता, भोपाल

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों से दो-दो वेटलैंड्स चिन्हित कर हेल्थ-कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य वेटलैंड्स प्राधिकरण एप्को ने चिन्हित वेटलैंड्स में से लगभग 50 तालाबों के हेल्थ-कार्ड केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिए हैं। देश में अब तक 500 वेटलैंड्स के हेल्थ-कार्ड बने हैं, जिनमें मप्र अग्रणी है। वेटलैंड्स के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य का पता लगाने के लिऐ वेटलैंड हेल्थ-कार्ड बनाए जा रहे हैं। वेटलैंड्स के हेल्थ-कार्ड के लिए भारत शासन द्वारा तय प्रारूप के अनुसार वेटलैंड्स का जलीय क्षेत्रफल, हाइड्रोलॉजी, जल की गुणवत्ता, जैव-विविधता और इस संबंध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय और आदेशों आदि का समावेश किया गया है। वेटलैंड की समस्त जानकारी को शामिल कर एक केटेगरी का निर्धारण किया जाता है।

120 तालाबों का चयन

वेटलैंड रिजुवेनेशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के 120 तालाबों और वेटलैंड्स को चिन्हित किया गया है। चिन्हित वेटलैंड्स के हेल्थ-कार्ड, संक्षिप्त प्रतिवेदन, एकीकृत प्रबंधन परियोजना आदि बनायी जा रही है।

एप्को जाच रहा गुणवत्ता

लगभग 50 तालाबों के हेल्थ-कार्ड भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। शेष वेटलैंड्स की जल गुणवत्ता की जांच के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एप्को प्रयोगशाला द्वारा कार्य किया जा रहा है।

इनका कहना है

मार्च-2021 तक सभी 120 वेटलैंड्स के हेल्थ-कार्ड पूरे करने के निर्देश दिए हैं। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एप्को को इस कार्य के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में मान्यता दी गयी है। मप्र के हेल्थ-कार्ड पूर्ण होने पर एप्को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य को भी इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता देगा।

हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री

नया कोर्सः चर्चा में आया उच्च शिक्षा विभागा का नवाचार

सरकार पढ़ाएगी मुर्गा-मुर्गी और भेड़-बकरी पालन का पाठ

संवाददाता, भोपाल

मप्र अजब है-सबसे गजब है। ये सुना ही होगा और नहीं सुना तो ये खबर पढ़कर आप यही कहेंगे। कमलनाथ सरकार द्वारा युवाओं को बैंड-बाजा और ढोर चराने का दावा किया गया था। लेकिन कुछ नहीं किया। अब शिवराज सरकार प्रदेश के कॉलेजों में पशुपालन के गुर सिखाने नया कोर्स शुरू करने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के कॉलेजो में कुत्ता, मुर्गा-मुर्गी, भेड़-बकरी पालने की ट्रेनिंग के लिए कोर्स शुरू किए जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय संस्थान नीम, हकीम, झोला-झाप डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे चुका है। इस वजह से विश्वविद्यालय काफी सुर्खियों में भी रहा।

वहीं सरकार के पशुपालन कोर्स कराने को लेकर कांग्रेस अब निशाना साध रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिक्षित युवाओं को पशुओं (मवेशियों) को पालने की ट्रेनिंग देकर युवाओं को सरकार अंधकार में ले जाना चाहती है। आईटी के जमाने में मवेशियों को पालने का कोर्स कराने की तैयारी कर रही है। पशुपालन ट्रेनिंग से अच्छा तो कमलनाथ का म्यूजिक बैंड सिखाने का प्लान था।

इनका कहना है

हमारा प्लान है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पशुपालन के भी गुर सिखाए जाएं। युवाओं को पशुपालन के गुर सिखाने वाले नए कोर्स के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा भी हो चुकी है। युवाओं को पशुपालन की ट्रेनिंग देना मप्र में नवाचार है।

डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री

सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेल रही है। ये सरकार रोजगार देने में असफल रही है। शिक्षित युवाओं को रोजगार की पशुपालन की ट्रेनिंग देने का काम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।

पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री

किसानों को गाजर के लिए नहीं मिल रहे कोल्ड स्टोरेज

» मंत्री ने भी दिया आश्वासन, समस्या का होगा समाधान » तर्कः कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण के लिए कोई नीति नहीं

संवाददाता, इंदौर

सरकार एक तरफ कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की फसल सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इंदौर में इसकी बानगी देखने को मिल रही है। किसानों की गाजर की फसल को कोल्ड स्टोरेज संचालक रखने से मना कर रहे हैं।

वे उन्हीं किसानों की गाजर की उपज को रख रहे हैं, जिन्होंने कांट्रेक्ट फार्मिंग के तहत उनसे अनुबंध किया है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज संचालक की लापरवाही से स्टोरेज में रखी गाजर और अन्य उपज खराब होती है तो उसकी भरपाई भी नहीं करते। इन समस्याओं को लेकर तिल्लौर बुजुर्ग के किसान मनीष पटेल, महेश दांगी, लखन पटेल और भगवती सिंह आदि ने उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के राज्य मंत्री भारतसिंह कुशवाह से गुहार लगाई। तब मंत्री ने किसानों की समस्या दूर करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन यह मजबूरी भी बताई कि कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण को लेकर अब तक सरकार की कोई नीति नहीं बनी है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

मांग रहे एडवांस

किसानों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज संचालक गाजर की हर बोरी पर 100 रुपए एडवांस मांग रहे हैं। साथ ही केवल 200 से 400 बोरी ही रखने को राजी हैं। थोड़ी-सी गाजर भी स्टोरेज में रखने के लिए किसानों को तीन-चार लाख रुपए एडवांस देना पड़ेंगे।

कहां से लाएं पैसा

प्रभावित किसानों का कहना है कि उपज बेचने से पहले ही किसान इतना पैसा कहां से लाएंगे। किसानों ने 10 से 15 बीघा की गाजर की बोवनी की है। एक किसान को चार हजार से लेकर पांच हजार बोरी गाजर का उत्पादन हो रहा है। बची हुई गाजर उनको औने-पौने दाम पर बेचना पड़ेगी। इससे हमें घाटा उठाना पड़ेगा।

■ बजट 2021: 2022 तक किसानों की आय होगी दोगुनी

आहत किसानों को राहत

» देश में छह साल में धान, गेहूं, दालों और कपास जैसी फसलों की खरीद कई गुना बढ़ी है।

» किसानों से खरीद लगातार बढ़ रही है, किसानों को किया जाने वाला भुगतान भी काफी बढ़ा है।

» गेहूं की खरीद पर 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ दिए थे, जो बढ़कर 2019-20 में 62,802 करोड़ पर पहुंचा।

» लाभ लेने वाले किसानों की संख्या भी 2019-20 के 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख पर पहुंच गयी।

भोपाल। बीते दो महीने से ज्यादा वक्त से केंद्र सरकार से नाराज किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बता रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए दावा किया कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है। 2021-22 बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपमेंट सेस (एआईडीसी) बढ़ाते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपए प्रति लीटर रखा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस काबुली चले पर 30 फीसदी, मटर पर 50 फीसदी, मसूर की दाल पर 5 फीसदी और रूई पर 5 फीसदी बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटा दी है। ऐसे में उभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत पर प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा।

देशभर में होगी स्वामित्व योजना

कुल मिलाकर उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एएक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है, ताकी कीमतों को लेकर कोई भार ना पड़े। 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपए तक किया जा रहा है। अब स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं, पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।

एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाया

आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं, उनमें एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है, लेकिन आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया है। वहीं, धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है और कृषि

उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा।

सरकार अपने लक्ष्य पर कायम

वित्त वर्ष 2021 में किसानों को गेहूं पर 75,100 करोड़ का भुगतान किया गया। गेहूं उगाने वाले 43.36 लाख किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी खरीद से लाभ हुआ, जो संख्या पहले 35.57 लाख थी। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से तीन गुना राशि किसानों के खातों में पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है और दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई।

43 लाख किसानों को लाभ मिला

धान की खरीद पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हजार करोड़ किया जा चुका है। इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है और 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था। इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ 2013-14 में खर्च किए थे। 2019 में 63 हजार करोड़ रुपए और अब यह 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है।

इस बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के काल में यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है। कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को मदद मिलेगा। महिलाओं के लिए बजट में सुविधाओं और समानता लाने के लिए प्रयास किया गया है। युवाओं को अवसर मिलेगा और यह इंफ्रास्टक्चर को भी सुधारने में मदद करेगा। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। किसानों को आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। इस बजट के दिल में गांव हैं, हमारे किसान हैं।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

वित्तमंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसके बाद किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर कोई शक नहीं रहना चाहिए। बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता और एपीएमसी को मजबूत करने की सरकार की कवायद बजट में दिखती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र का बजट भी बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल ना केवल कृषि बजट बढ़ाया जा रहा है, बल्कि योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी पूरा ध्यान है। इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को मिलेगा।

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

ऐतिहासिक बजट। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आर्थिक विकास की एक नई सुबह देखी है। सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए, निर्णय लिए गए, जो न केवल वर्तमान में लाभान्वित करेंगे बल्कि भविष्य में भी हमें लाभान्वित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उठाए गए कदम और व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगी।

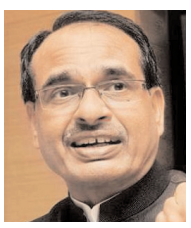

शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मप्र

कृषि के काले कानूनों में काला क्या है?

डॉ. आनंद शुक्ल

विपक्षी दल यह बताने की स्थिति में नहीं कि कृषि कानूनों में खामी क्या है? उसी तरह किसान संगठन भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या खराबी है? वे केवल यही रट लगाए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।

यह अच्छा हुआ कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों और नए कृषि कानूनों के विषय में व्यापक बहस हुई। इस बहस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन के समय यदि विपक्ष बगलें झांकने वाली स्थिति में दिखा तो इसी कारण कि वह कृषि कानूनों को लेकर दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है और यह बताने की स्थिति में नहीं कि इन कथित काले कानूनों में काला क्या है? विपक्षी दल अनुबंध खेती के प्राविधान का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं कि आखिर पंजाब समेत करीब दो दर्जन राज्यों ने अनुबंध खेती संबंधी कानून क्यों बनाए हुए हैं? क्या यह विचित्र नहीं कि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी पंजाब के किसान संगठनों की ही है। साफ है कि किसानों का

आंदोलन राजनीति प्रेरित और ऐसी अफवाहों पर आधारित है कि यदि कृषि कानून लागू हुए तो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। विपक्ष को इससे अवगत होना चाहिए कि इस दुष्प्रचार का सहारा केवल किसान संगठन ही नहीं ले रहे, बल्कि वे देश विरोधी ताकतें भी ले रही हैं, जो भारत को बदनाम करने का अभियान चला रही हैं। आखिर कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार में हिस्सेदारी करके विपक्ष किसके हितों की पूर्ति कर रहा है? यह कहां की समझदारी है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के फेर में देश विरोधी तत्वों के हस्तक्षेप की अनदेखी कर दी जाए? सवाल यह भी है कि जो विपक्षी दल राज्यसभा में किसानों के मसले पर चर्चा के लिए राजी हो गए, वही लोकसभा में हंगामा क्यों करने में लगे हुए हैं? कृषि कानूनों और किसानों को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहना तो यही बताता है कि वे बहस से भाग रहे हैं। जिस तरह विपक्षी दल यह बताने की स्थिति में नहीं कि कृषि कानूनों में खामी क्या है, उसी तरह किसान संगठन भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या खराबी है? वे केवल यही रट लगाए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। यह हठधर्मिता के अलावा और कुछ नहीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सरकार तीनों कृषि कानूनों के आपत्तियों वाले प्राविधान न केवल संशोधन को तैयार है, बल्कि डेढ़ साल के लिए इन कानूनों के अमल को भी रोकने को राजी है। किसान नेताओं को यह भी मंजूर नहीं। वे कृषि कानूनों की समीक्षा के प्रस्ताव को भी स्वीकार करने से इन्कार कर रहे हैं, जबकि इससे उनके ही हित सधेंगे।

आर्थिक बहाली का वाहक बनेगा यह बजट

मुकेश बुटानी

जिस पृष्ठभूमि में यह बजट पेश किया गया है, उसे देखते हुए निर्मला सीतारमण को यह अनूठा अवसर मिला कि वह ऐसी चिंताओं के असर में आए बगैर इस मौके का भरपूर फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं। सरकार की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि महामारी के दौरान करों के संग्रह में आई कमी और राजस्व घाटे में हुई ऐतिहासिक वृद्धि के बावजूद उसने कॉर्पोरेट टैक्स एवं अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करने की अपनी ललक पर लगाम लगाए रखी। इस पर आम सहमति थी कि अनुमानित कर संग्रह में आई भारी कमी की भरपाई के लिए एक नया कर या उपकर लगाना जरूरी है। हालांकि वित्त मंत्री ने राजस्व जुटाने के लिए कुछ दूसरे नवाचारी तरीके ईजाद किए हैं जिनमें जमीन की बिक्री एवं विनिवेश पर नए सिरे से जोर देना, अनुपालन बोझ को कम कर कारोबारों को फलने-फूलने वाला माहौल देना शामिल है। कर बोझ न बढ़ाने का फैसला भारतीय कंपनी जगत की धारणा को मजबूत करने और खपत एवं आर्थिक रिकवरी के नजरिये से अहम होगा।

इस बजट ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का आगाज कर भौतिक, वित्तीय एवं पूंजीगत ढांचे पर मजबूती से जोर दिया है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की प्रगति जांचने के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड के जरिये निवेशकों एवं रेटिंग एजेंसियों के बीच भरोसा पैदा किया जाएगा और गैर-कर राजस्व जुटाने के लिए सरकार की गंभीरता का भी अहसास होता है। मेट्रो, समर्पित मालढुलाई गलियारों, राजमार्गों एवं आर्थिक गलियारों के गठन समेत महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के लिए विशेष फंड आवंटित किए जाने और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाए जाने से अर्थव्यवस्था को मेक इन इंडिया की राह पर डाला जा सकेगा।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के भागीदारों को समर्थन देते हुए एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाया जा रहा है जो तनावग्रस्त समय एवं इतर मौकों पर भी निवेश योग्य ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा अन्यथा तरलता में भारी वृद्धि होगी। ढांचागत ऋण फंड अब कर-सक्षम ढंग से जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर पाएंगे। छोटे कर्जदारों को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है क्योंकि इसने सराफेसी कानून के तहत कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम कर्ज सीमा को घटाकर 20 लाख रुपए कर दिया है।

बजट में निवेशक चार्टर लाने की बात कही गई है। यह चार्टर सेवा मानकों पर अमल को सुनिश्चित करने एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने से संबंधित मानक तय करने, तर्कसंगत बनाने एवं स्पष्टता लाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने की उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी कुछ सुरक्षा उपायों के साथ अधिसूचित किया जाएगा। बीमा कंपनी के बोर्ड एवं अहम प्रबंधकीय पदों में स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय किए जाएंगे।

बजट में फंसे कर्ज की बढ़ती समस्या से निपटने एवं तनावग्रस्त परिसंपत्ति के निपटारे के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी के गठन जैसे कुछ साहसिक प्रस्ताव भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक पहले से ही तय नियामकीय ढांचे के तहत ऐसे बैड बैंक के प्रशासन में पहले अपना भरोसा जता चुका था। लेकिन बैंक एवं दूसरे देनदारों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि समुचित अनुपालन संस्कृति का पालन किया जाए और शुरुआती दौर में ही जोखिमों को चिह्नित कर लिया जाए ताकि कर्ज डूबने की यह समस्या फिर से न पैदा हो।

राजस्व जुटाने के नवाचारी तरीकों में गैर-प्रमुख सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है जिसमें मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं की जमीन हैं। इनकी बिक्री के लिए विशेष उद्देश्य इकाई का गठन किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की जो घोषणा 2020 में ही की गई थी वह सरकार के लिए राजस्व जुटाने का सबसे बड़ा मौका हो सकती है। वित्त मंत्री ने नीति आयोग के सहयोग से रणनीतिक विनिवेश की कोशिशें नए सिरे से शुरू करने और घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाइयों को बंद करने की बात कही है। ऐसे प्रयास किए जाने पर वृहद-आर्थिक संकेतकों में सुधार आएगा और राजस्व के लिए कर संग्रहों पर निर्भरता भी घटेगी।

समावेशी विकास की दिशा में अपना अभियान आगे बढ़ाने के क्रम में न्यूनतम मजदूरी का विस्तार एवं सभी श्रेणियों के कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाना निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को मानक बनाना, मॉडल स्कूलों का विकास और राष्ट्रीय शिक्षा पर बाल शिक्षा ढांचे के निर्माण में अहम कदम साबित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लहर पर सवार होकर अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के जरिये कौशल, तकनीक एवं ज्ञान के हस्तांतरण को बढ़ावा देने वाले उपाय सराहनीय हैं। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने एक विवाद निपटान समिति के गठन की बात कही है जिसे छोटे करदाताओं के विवादों को दूर करने का जिम्मा दिया जाएगा। व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत खत्म करने वाली पहचान-रहित कर आकलन योजना का प्रयोग सफल रहने से उत्साहित वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपील पंचाट केंद्र बनाने की घोषणा की है जहां पर सभी कार्य-व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ही किए जाएंगे। इससे भारत फेसलेस आकलन एवं अपील के मामले में अग्रणी देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जो अन्य अदालतों एवं पंचाटों के लिए भी एक नजीर साबित होगा। सरकार ने जीएसटी एवं आयकर दोनों देने वाले करदाताओं पर ऑडिट एवं अनुपालन बोझ घटाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।

सरकार की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि महामारी के दौरान करों के संग्रह में आई कमी और राजस्व घाटे में हुई ऐतिहासिक वृद्धि के बावजूद उसने कॉर्पोरेट टैक्स एवं अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करने की अपनी ललक पर लगाम लगाए रखी। इस पर आम सहमति थी कि अनुमानित कर संग्रह में आई भारी कमी की भरपाई के लिए एक नया कर या उपकर लगाना जरूरी है।

ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में भी मिलेगी मदद

अरविंद चतुर्वेदी

भारतीय मनीषा में असली समृद्धि के मायने को आधुनिक युग में एक बार फिर मुहर लगी है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति को ही सबसे बड़ी पूंजी माना गया है, लेकिन उपभोक्तावाद की दुनिया ने इस सिद्धांत को तज दिया। तज क्या दिया, एक तरीके से बिसार दिया। हम आभासी समृद्धि के पीछे दौड़ने लगे और वास्तविक समृद्धि को उजाड़ते गए। आज जब देश की शीर्ष न्यायिक संस्था ने विशेषज्ञों की समिति के निष्कर्ष के आधार पर यह तय कर दिया कि एक वयस्क पेड़ हर साल करीब 75 हजार रुपये की कीमत का लाभ पहुंचाता है तो पता नहीं अपने किए पर उन लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि नहीं, जिन्होंने जंगलों को उजाड़ आभासी विकास का रास्ता अपनाया है।

बात बहुत सीधी थी, लेकिन सबके समझ में नहीं आई। हमारे ऋषि-मुनियों ने अपने आचार, विचार और व्यवहार से हमको सिखाया, समझाया। लेकिन भौतिकता के फेर में हम 'न माया मिली न राम' के शिकार हो गए। ऋषियों-मुनियों के आश्रम तो अब दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन अगर आप उनके चित्र देखें तो हरियाली और पेड़-पौधों से आच्छादित होते थे। ये उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हर जरूरत की पूर्ति करते थे। यही उनकी पूंजी होती थी। इस मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्थापित किया है।

दरअसल, पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई। यह याचिका बंगाल सरकार के उस कदम के खिलाफ थी जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से पांच रेलवे ओवरब्रिज बनाने के नाम पर 356 पेड़ों की बलि तय हो चुकी थी। शीर्ष अदालत ने इन पेड़ों की कीमत तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने बताया कि एक पेड़ हर साल 74,500 रुपए का लाभ पहुंचाता है। पेड़ों द्वारा वायुमंडल में अवमुक्त की जा रही ऑक्सीजन की कीमत 45 हजार रुपए है।

अब आप कल्पना कीजिए कि असली धनवान कौन है। जंगलों को सहेजने-संवारने वाले हमारे आदिवासियों से धनी कौन है आज। भारी-भरकम बैलेंस शीट वाले देश के उद्योगपतियों के खाते में जमा धन से कितने ऐसे पेड़ खरीदे जा सकते हैं। सरकार का संबंधित मंत्रलय पेड़ों की कीमत का आकलन नेट प्रजेंट वैल्यू के आधार पर करता है जो बहुत ही संकीर्ण है। इस गणना के अनुसार एक हेक्टेयर या 2.4 एकड़ क्षेत्र में खड़े पेड़ों की कीमत का आकलन बहुत घने जंगलों के लिए अधिकतम 56 लाख और खुले जंगल के लिए इतने क्षेत्र में मौजूद पेड़ों की कीमत 27 लाख आंकी जाती है। कोई भी यह सहज आकलन कर सकता है कि एक घने जंगल के 2.4 एकड़ में कितने पेड़ हो सकते हैं और यदि एक पेड़ की सालाना लागत करीब 75 हजार हो तो उस क्षेत्र के कुल पेड़ों की उनके पूरे आयुकाल की लागत क्या होगी? कोई भी सरकारी परियोजना ऐसी नहीं है जिसके सिरे चढ़ने में प्रकृति का विनाश नहीं होता हो। पेड़ों का काटा जाना तय होता है। कई मामलों में तो पूरी परियोजना की लागत पेड़ों की इस नई कीमत से बहुत कम हो जाएगी। एक जमाना था जब दुनिया का हर भूभाग वनों से आच्छादित था। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती जरूरत के चलते हरियाली के रकबे का अनुपात कम होता गया। यह प्रवृत्ति दुनिया के लगभग सभी देशों में दिखी। भारत जैसे प्रकृति प्रेमी देश में भी जरूरत प्रेम पर हावी रही। हमने ठाना कि देश के भूभाग का एक तिहाई रकबा जंगल से आच्छादित करके रहेंगे।

टमाटर की खेती से निराश किसान ने केले में लगाया दांव, -पौधे देखकर दिल्ली के व्यापारी ने एक करोड़ कीमत लगाई

18 लाख के केले की फसल को मिला एक करोड़ का ऑफर

बृजेश ठाकुर, रायसेन

कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम केवलझिरी के किसान जोगेंद्र सिंह ने आपदा में अवसर खोज लिया। उन्होंने पहली बार 15 एकड़ खेत में केले की खेती करते हुए 18 लाख की लागत लगाई और अब उनकी फसल के दाम आनलाइन नीलामी में दिल्ली के एक व्यापारी ने एक एकड़ रुपए लगा दिए हैं। पौधे इतनी अच्छी तरह से तैयार हुए हैं कि खेती-किसानी के जानकार इन्हें अच्छी फसल की गारंटी मान रहे हैं। कृषि विज्ञानी किसान के इस प्रयासों पर शोध करने की योजना बना रहे हैं। जोगेंद्र पहले टमाटर की खेती करते थे, लेकिन दाम अच्छे नहीं मिल पाते थे। कोरोना लॉकडाउन में जब सभी ओर मायूसी थी, तब उन्होंने केले की फसल में हाथ आजमाया। बुरहानपुर में रहने वाले उनके कुछ रिश्तेदारों ने जानकारी दी थी कि इस बार केले की फसल लॉकडाउन के कारण अच्छी तरह से नहीं लग नहीं पाई है। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि अभी केला की रोपाई नहीं हुई है तो सीजन पर फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसलिए पहली बार केले की फसल लगाने का साहस जुटाया।

15 एकड़ में 25.5 हजार पौधे लगाए

उद्यानिकी विभाग से तकनीकी सलाह लेकर जुलाई 2020 में केले के पौधों का रोपण कर दिया। उनके 15 एकड़ के खेत में 25 हजार 500 पौधे लगे हैं। सही समय पर खाद, पानी का उपयोग करने से पौधे अब अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जब जोगेंद्र ने अपने खेते के केले के पौधों के फोटो व वीडियो व्यापारियों को भेजे तो खुद व्यापारियों ने प्रत्येक पौधे में 30 से 35 किलो तक फल लगने का अनुमान बताया है।

इनका कहना है

शोधार्थियों व कृषि विज्ञानियों के साथ केवलझिरी पहुंचकर फसल का जायजा लिया था। दरअसल रायसेन जिले की चिकनी मिट्टी और जलवायु केले की खेती के लिए उपयुक्त है। जोगेंद्र के खेत की केले की फसल पर शोध कराया जाएगा।

– **डॉ. स्वप्निल दुबे**, प्रमुख, जिला कृषि विज्ञान केंद्र, रायसेन

जोगेंद्र के खेत में लगे केले की फसल को हमने देखा है। प्रत्येक पौधे में 30 से 35 किलो फल आने का अनुमान है।

– **नरेश सिंह तोमर**, सहायक संचालक, उद्यानिकी विभाग, रायसेन

पौधे की मोटाई के हिसाब से फल लगते हैं। जोगेंद्र ने अपनी फसल का ऑनलाइन मूल्य एक करोड़ 10 लाख रुपए रखा था। मैंने एक करोड़ दाम लगा दिए हैं। हमें जोगेंद्र सिंह के खेत पर लगी केले की फसल की अच्छी पैदावार पर भरोसा है। हम 20 साल से यही कारोबार कर रहे हैं।

सतपाल सिंह, व्यापारी, दिल्ली

चना, अरहर और मटर में इल्ली का बढ़ा प्रकोप

प्रकाश शिवहरे, होशंगाबाद

नर्मदांचल के प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र में इस बार दलहनी फसलों की पर्याप्त मात्रा में बोवनी की गई है। कृषि विभाग के अनुसार इस बार चना की बोवनी 25 हजार हेक्टेयर में अरहर 6 हजार, मटर 2 हजार व अन्य दलहनी फसलें करीब 4 हजार हेक्टेयर में बोई गई हैं। बीच-बीच में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अलग-अलग फसल में अलग तरह के रोग लगने से फसलों को नुकसान होना बताया जा रहा है। जिले में करीब 38 हजार हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बोवनी हुई है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि कभी ठंड तेज तो कभी धूप तेज निकल रही है। उससे पूर्व भी मौसम में गडबड़ी बनी रही, जिससे दलहनी फसलों को नुकसान हो रहा है। कुछ खेतों में तो चने की फसल सूखने जैसी हो गई है। खासकर नदियों और नाले के किनारे वाली फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। किसानों का अनुमान है कि अभी तक दलहनी फसलों को करीब 10-15 फीसद तक नुकसान हो गया है। किसान नेता नरेंद्र पटेल ने बताया कि दलहनी फसलों में इल्ली की शुरुआत हुई थी, तब ही कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। लेकिन कुछ किसानों की चने की फसल में सूखा रोग लगने से फसल खराब हो रही है। कुछ किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो गया है। किसान मनोहर केमइया का कहना है कि खेती करना अब घाटे का सौदा होता जा रहा है, क्योंकि कभी अतिवृष्टि तो कभी इल्ली या फिर तरह-तरह के रोग लग जाते हैं। जिससे क्षेत्र के अन्नदाताओं के सामने मुसीबत ज्यादा आती जा रही है।

- नर्मदांचल के प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र में इस बार दलहनी फसलों की पर्याप्त मात्रा में बोवनी हुई
- मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अलग-अलग फसल में अलग तरह के कीट लग रहे

इनका कहना है

जिस प्रकार कुछ जगह दलहनी फसलों में हल्की फुल्की शिकायत आ रही है वह मौसम का असर हो सकता है, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। बादल होने के कारण कुछ स्थानों पर कीट का प्रभाव था, अब बादल भी छट गए हैं। अन्य फसलें ठीक हैं।

जेएस कासदे, सहायक संचालक कृषि

- जैविक खेती का तरीका सीखने बेटे को यूपी के कन्नौज भेजा

कांट्रैक्ट फार्मिंग से बीहड़ में किसान हुए आत्मनिर्भर

- उप्र के व्यापारियों के लिए उगा रहे अमरूद-पपीता

किसान ने अपनी फसल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए

नीरज शर्मा, भिंड

नए कृषि कानूनों के विरोध की एक वजह कान्ट्रैक्ट फार्मिंग (अनुबंध पर कृषि) है, लेकिन इसे अपनाकर प्रदेश के भिंड जिले के किसान महज दो साल में अपनी सालाना आय दो से बढ़ाकर पांच लाख कर ली। बीहड़ की जमीन कम उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन दुल्हागन गांव के विष्णु शर्मा ने मेहनत और नए तरीके अपनाकर अपना जीवन बदल लिया। आमतौर पर यहां किसान सालभर में दो पारंपरिक फसल गेहूं और सरसों ही ले पाते हैं, लेकिन विष्णु साल में चार फसलें ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से अनुबंध कर फलों का उत्पादन कर रहे हैं। विष्णु का दावा है कि आयुर्वेद दवाओं में इस्तेमाल होने वाली सफेद मूसली के लिए और जैविक (ऑर्गेनिक) सब्जियों के लिए बड़ी कंपनियों ने भी उनसे संपर्क किया है। विष्णु के पास 70 बीघा जमीन है। वे वर्ष 2017 से 50 बीघा में गेहूं, उड़द, मूंग और तिल्ली की फसल ले रहे हैं।

यूपी के व्यापारी ने ही दिए पेड़

20 बीघा जमीन को भी खेती लायक बनाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा के व्यापारियों के लिए उन्होंने खेत की मेड़ पर पपीते के करीब 300 और अमरूद के 270 पेड़ लगाए हैं। पौधे इटावा के व्यापारी ने ही उपलब्ध कराए और अनुबंध के तहत फल भी वे ही खरीद रहे हैं। विष्णु को बीते वर्ष अमरूद और पपीते से दो लाख रुपए की आमदनी हुई। अनार और आंवले से भी एक लाख कमाए।

बेरोजगारी में छोड़ा था गांव

पारंपरिक खेती में ज्यादा लाभ नहीं होने के कारण विष्णु ने वर्ष 2000 में गांव छोड़कर नजदीकी फूफ कस्बे में रहकर व्यवसाय किया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। वर्ष 2017 में नए तरीके से खेती करने का विचार बनाया। इटावा में फल व्यापारियों से संपर्क हुआ। उन्होंने रासायनिक खाद के प्रयोग के बिना उगाए अमरूद और पपीता की मांग की। विष्णु ने बेटे को भी जैविक खेती का तरीका सीखने उत्तर प्रदेश के कन्नौज भेजा। अब पूरा परिवार खेत के बीच बने बड़े से घर में एक साथ रहता है।

तकनीक ने बढ़ाई आमदनी

खेतों में नकदी फसलें उगाईं तो उनकी सुरक्षा की बड़ी चुनौती सामने आई। उन्होंने हरियाणा के किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली झटका तकनीक का सहारा लिया। इसमें खेत के चारों ओर लोहे का पतला तार लगाया जाता है। यह तार विशेष यंत्र से जुड़ा होता है। इसके संपर्क में आने से जानवरों को केवल हल्का करंट का झटका लगता है और सायरन बजता है। इससे आवारा जानवर फसलों से दूर रहते हैं। निगरानी के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं।

इनका कहना है

पतंजलि ने सफेद मूसली के लिए प्रति बीघा डेढ़ लाख देने का प्रस्ताव दिया है। बिग बाजार ने जैविक तरीके से करेला और गाजर उगाने के लिए संपर्क किया है। दोनों प्रस्तावों के संबंध में मैं तैयारी कर रहा हूं।

विष्णु शर्मा, किसान, भिंड

बीहड़ में यहां के किसान विष्णु शर्मा ने सराहनीय कार्य किया है। उनके नवाचारों से जिले के अन्य किसान भी सीख सकते हैं। अब उनकी आय भी दो गुना हो गई है।

रामसुजान शर्मा, सहायक संचालक, कृषि, भिंड

फसल देखकर किसान ने कहा-स्वस्थ धरा तो खेत हरा...

विंध्य में लहलहा रही पूसा की सरसों

सिर्फ ढाई महीने की फसल में बंपर पैदावार के आसार

संवाददाता, रीवा। शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर हो अन्नदाता के सपने को रीवा जिले के किसान साकार कर रहे हैं। दरअसल, तहसील मऊगंज के ग्राम नहरो के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने अपने सात एकड़ खेत में नबंवर माह के अंतिम में सरसों की पूसा 31 किस्म की बोवनी की थी। जो अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। यह फसल सिर्फ ढाई माह में ही तैयार हो गई है। किसान ने करीब सात एकड़ में पीले सरसों की बोवनी की थी, लेकिन मौसम की बेरुखी और पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण दो एकड़ में ही फसल बची है। जो अब पकने की कगार पर पहुंच गई है। किसान अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि यह संभव हुआ है सरसों की अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध होने से। वो अपने खेत में वर्षों से परम्परागत रूप से खेती करते आ रहे थे। हाल के कुछ वर्षों से परम्परागत खेती की लागत ज्यादा होती जा रही थी। इसी को देखते हुए वो एक बार दिल्ली स्थिति पूसा कृषि केंद्र गए थे। जहां से पीले सरसों के बीज लाए। उसी सरसों को प्रयोग के तौर पर इस साल बोवनी की। लेकिन पानी की कमी के कारण सिर्फ दो एकड़ में ही फसल बची है।

कुएं में पानी नहीं

किसान ने बताया कि पत्थरों के बीच में एक कुआं है, लेकिन बरसात के बाद उसमें पानी लगभग सूख जाता है। मोटर सिर्फ एक घंटे चल पाता है। इस कारण पूरे खेत की सिंचाई भरपूर नहीं हो पाती है।

लाल मिट्टी में सोना

किसान ने बताया कि उनके खेत की लाल मिट्टी है। जिसमें सभी फसल उगाई जा सकती हैं। खासकर सरसों और पीली सरसों का भारी मात्रा में उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। पानी की कमी नहीं होती तो लगभग 20 एकड़ में इसी तरह की सरसों लहलहा रही होती।

मिर्च जैसी बालियां

किसान के खेत में लहलहा रही सरसों में मिर्च जैसी बालियां लगी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की फसल लगेगी। उन्होंने बताया कि फसल ऐसी लगी है कि अधिकांश पेड़ भी गिर गए हैं। खेत में पूसा की सरसों फसल लहलहाने की आस-पास के किसानों में भी चर्चा है। वे भी सरसों की इस किस्म को आजमाने की सोच रहे हैं।

बंपर पैदारवार के आसार

किसान का कहना है कि कीट पतंगों और बीमारियों से मुक्त खेतों में लहलहाते सरसों के पौधे देखकर इस साल बंपर पैदावार के आसार नजर आ रहे हैं। अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। इस बार हमारी मेहनत का वास्तविक फल मिलने जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार अच्छी पैदावार हो सकती है।

पूसा की खेती देखकर हुआ प्रभावित

कृषि केंद्र पूसा में आधुनिक तकनीकि से हो रही खेती को देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ। इसके बाद मैंने तय किया कि इसी तर्ज पर अब खेती करूंगा। जिसकी शुरुआत मैंने पूसा सरसों 31 की बोवनी अपने खेत में की है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी पैदावार होगी। मेरा मानना है कि आज के समय में किसानों को अंतरवर्ती खेती करनी चाहिए। साथ ही समय-समय पर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेते रहना चाहिए। ताकि फसल के उत्पादन में कोई कमी न आ सके।

अनिल कुमार मिश्र, प्रगतिशील किसान, नहरो

महंगी बिकेगी सरसों

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पूसा की सरसों की पैदावार अधिक है। अपने गुणों के कारण यह आम सरसों से महंगी भी बिकेगी। सामान्य सरसों एक बीघा में सवा क्विंटल तक निकलती है। लेकिन पूसा की सरसों की पैदावार दो क्विंटल प्रति बीघा से भी अधिक है। यह बंपर पैदावार देने वाली प्रजाति है।

कैसे करें तैयारी: सरसों की बोवनी के लिए सबसे पहले एक बार सामान्य जुताई करना चाहिए। इसके बाद दो जुताई हैरो से 1 जुताई रोटावेटर से करना चाहिए।

खाद और उर्वरक: सरसों की अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 40 किलो, पोटाश 20 किलो के अतिरिक्त 14 से 16 किलो सल्फर भी डालना चाहिए।

समय और बीज मात्रा: प्रति एकड़ दो किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं बोवनी से पहले बीजों को अनुशंसित दवाई बीजोपचार कर लेना चाहिए। इसकी

बोवनी अक्टूबर-नबंवर तक कर देना चाहिए। इसकी बोवनी के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बीज को मिट्टी के अंदर 2-3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए।

निराई-गुड़ाई एवं सिंचाई: अन्य फसलों की तरह इसकी भी समय-समय पर निराई-गुड़ाई करना चाहिए। वहीं इसमें 2-3 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। उपज की बात करें तो प्रति एकड़ 5 से 10 क्विंटल तक ली जा सकती है।

संपर्क: सरसों की बोवनी के लिए अधिक जानकारी के लिए किसान अनिल कुमार मिश्रा से **मोबाइल नंबर 9893192453** पर इच्छुक किसान बात कर सकते हैं।

प्रदेश में शुरू होगा पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन

» पंजाब, हरियाणा-उत्तराखंड के बाद मध्यप्रदेश आया आगे » 15 किलोमीटर फ्रिक्वेंसी में प्रसारित होंगे कार्यक्रम

दिव्या मिश्रा, ग्वालियर

कृषि के क्षेत्र में अग्रणी मप्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने और वोकल को लोकल बनाने अब प्रदेश का राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आगे आया है। दरअसल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के बाद मध्यप्रदेश में भी खेती किसानी पर आधारित सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू होने जा रहा है। राजमाता विजयाराजे कृषि विवि ने रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए केंद्र और आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) में आवेदन कर दिया है। 15 किमी फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो स्टेशन के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थान भी चयनित कर लिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के परिसर के बाहर बन रहे एग्रीकल्चर तकनीक सेंटर में रेडियो स्टेशन बनाया जाएगा। 15 लाख की लागत से तैयार होने वाले इस स्टेशन में टॉवर और प्रसारण केंद्र तैयार होगा। इसी परिसर में एग्रीकल्चर तकनीक सेंटर भी बनाया जाएगा। यहां किसानों के लिए फसल के बीज, तकनीक, बीमारी उसका निवारण, यंत्र, खाद आदि की जानकारी दी जाएगी और इसे उपलब्ध भी कराया जाएगा। यदि कोई बीज, खाद या यंत्र उपलब्ध नहीं है तो उस स्थान की जानकारी दी जाएगी, जहां पर किसान को उक्त सामान मिल सकेगा।

- किचन गार्डन और रूफ टॉप फार्मिंग के लिए उपयोगी
- किसान का तजुर्बा किसानों के बीच शेयर कराया जाएगा
- 15 लाख आएगी लागत, टॉवर व प्रसारण केंद्र तैयार होगा
- किसानों को समझाने स्थानीय भाषा में प्रसारण कराया जाएगा

वोकल फॉर लोकल

विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि रेडियो प्रसारण का समय दो घंटे का रहेगा। इसमें कृषि तकनीक के साथ सोशल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। स्थानीय भाषा में प्रसारण कराया जाएगा जिससे किसानों को आसानी से बात समझ में आए। ऐसे किसान जिन्होंने कृषि तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाई उनका तजुर्बा किसानों के बीच शेयर कराया जाएगा। शहर में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें किचन गार्डन व रूफटॉप फार्मिंग शौक है। उनके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की मदद से किचन गार्डन व रुफटॉप फार्मिंग की तकनीक बताई जाएगी। जिससे लोग कम जगह में ताजा फल,सब्जी उगा सकें।

इनका कहना है

सामुदायिक रेडियो स्टेशन से विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उनकी भाषा और बोली में कृषि के क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीक, बीज, फसल की बीमारियां और उनका उपचार सहित कृषि यंत्रों की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद चालू कर दिया जाएगा। सामुदायिक रेडियो की योजना देश में केंद्र सरकार ने 2006 में शुरू की थी।

डॉ.एसके राव के अनुसार, कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि प्रदेश में पहला विवि होगा जो रेडियो के माध्यम से किसानों के बीच कृषि तकनीक पहुंचाएगा। किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलेगी। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। कृषि योजनाएं अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचेगी। रेडियो स्टेशन का काम अंतिम चरण में है।

डॉ. वायडी मिश्रा, कृषि विस्तार अधिकारी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि

मंत्रियों और अधिकारियों का औषधीय पौधों से स्वागत करेगा आयुष विभाग

भोपाल। आयुष विभाग की बैठकों में विभाग के मंत्री और अफसरों का स्वागत अब गुलदस्ते या फूल मालाओं से नहीं होगा, बल्कि सुसज्जित औषधीय पौधों के गमले से किया जाएगा। आयुष विभाग की प्रमुख सचिव सहा आयुक्त आयुष संचालनालय करलिन खोंगवार देशमुख ने सभी संभागीय आयुष अधिकारियों, अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद, यूनानी, फर्मेसी भोपाल और ग्वालियर, रजिस्ट्रार आयुर्वेद, होम्योपैथी बोर्ड और शासकीय, स्वशासी आयुष महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। गौरतलब है कि विभागीय समीक्षा बैठक में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने गुलदस्ते, फूल माला से स्वागत की परंपरा को बदलने के लिए कहा था। मंत्री का मानना है कि फूल गुलदस्ते और माला से होने वाले स्वागत का खर्च व्यर्थ जाता है। इसलिए इसकी जगह सुसज्जित औषधीय पौधे के गमले से अतिथियों का स्वागत किया जाए ताकि उसके उत्पादन का लाभ लिया जा सके।

चैन फेंसिंग पर मंत्रणा

भोपाल। उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से सौजन्य भेंट की। राज्य मंत्री कुशवाह ने केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर से प्रदेश में उद्यानिकी फसलों से जुड़े किसानों के खेतों में सुरक्षा के लिए चेन फेंसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा की और केन्द्रीय मंत्री तोमर से केन्द्र सरकार से योजना में सहयोग दिलाने का अनुरोध किया।

बांस की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय

सफलता की कहानीः कटंग बांस के 4 हजार पौधे लगाकर विजय पाटीदार ने की देखभाल

संजय शर्मा, खरगोन

निमाड़ इलाके की पहचान नीम के पेड़, मिर्च और कपास की प्रचलित फसलों से होती आई है, पर इस क्षेत्र को बांस के माध्यम से नई पहचान दिलाने का बीड़ा खरगोन जिले के ग्राम मेनगांव के विजय पाटीदार ने न केवल उठाया है, बल्कि वे इसमें कामयाब भी रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में दो साल पहले कटंग बांस के 4 हजार पौधे लगाकर इसकी पूरी मशक्कत के साथ देखभाल की। इसका परिणाम यह निकला कि इन्होंने सब्जी के खेती में पौधा सहारा देने के लिए काम आने वाले 75 हजार रुपए के बांस के डंडों का उत्पादन कर लिया है। विजय को बांस के पौधे लगाने की प्रेरणा इस बात से मिली कि परम्परागत फसलों में काफी मेहनत के बावजूद कई बार घाटा सहन करना पड़ता था। इसलिए वे लगातार इस खोज में लगे रहते थे कि

ऐसी कौन-सी फसल पर काम करें, जहां कम मेहनत और कम रिस्क में ज्यादा लाभ मिले। इनकी यह खोज बांस की फसल पर आकर पूरी हुई। मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन बांस के पौधे लगाने पर तीन साल में प्रति पौधा 120 रुपए का अनुदान देता है। इससे किसान की लागत बेहद कम हो जाती है। इसकी खासियत यह भी है कि इस फसल पर कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता, जिससे महंगी दवा और रासायनिक खाद के उपयोग से मुक्ति मिल जाती है।

चार साल में 40 लाख की फसल

बांस लगाने के चौथे साल से प्रति भिर्रा न्यूनतम 10 बांस तकरीबन 40 फीट लम्बे प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह 40 हजार पौधों से 40 हजार बांस उपलब्ध हो जाते हैं। प्रति बांस 100 रुपए के मान से बिक्री होने पर लगभग 40 लाख की फसल मिलेगी। इन बांसों को खरीददार स्वयं खेत तक आकर ले जाया करते हैं। बांस की फसल से चौथे साल में प्रति एकड़ एक हजार क्विंटल बांस की सूखी पत्ती प्राप्त होती है।

मध्यप्रदेश में सौर्य ऊर्जा से बनी बिजली रेलवे को देगी सरकार

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आगर-मालवा, शाजापुर और नीमच जिले में स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। डंग ने कहा परियोजना पूर्ण होने पर राज्य को सस्ती बिजली मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। इस सौर परियोजना का कार्य नवम्बर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्पादित बिजली प्रदेश के अतिरिक्त भारतीय रेलवे को भी दी जाएगी। आगर-मालवा जिले में 550 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने के लिए आगर तहसील के ग्राम माधवपुर, बिजनाखेड़ी, कसाइ देहरिया, करवाखेड़ी, लाड़वन, पिपलियाकुमार, दुधपुरा की 578 हेक्टेयर राजस्व भूमि और किसानों से 51 हेक्टेयर भूमि सहमति के आधार पर ली जाएगी। इसी तरह सुसनेर तहसील के ग्राम पालड़ा, नाहरखेड़ा उमरिया पिपल्यान की 775 हेक्टेयर भूमि शामिल है। आगर-मालवा जिले में कुसुम बी योजना के प्रथम चरण में 69 सोलर पम्प और द्वितीय चरण के 288 पम्प स्थापित किए गए हैं। यहां 29 सोलर पम्प स्थापनाधीन हैं।

» गौ-संवर्धन और गौ-संरक्षण के क्षेत्र में सरकार का बड़ा कदम

» मुख्यमंत्री गौसेवा योजना गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी

» पंचायतों से लेकर मंत्रालय तक के दफ्तरों में होगा इस्तेमाल

गौमाता के लिए संजीवनी का काम करेगा 'गौ-फिनायल'

भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अब गौ-फिनायल से साफ-सफाई होगी। इस आशय का आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि अब प्रदेश के सारे सरकारी दफ्तर केमिकल युक्त फिनायल की जगह गौमूत्र से बने गौ-फिनायल से साफ होंगे। शिवराज सरकार के इस फैसले को गौ-संवर्धन और गौ-संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नवंबर में आयोजित पहली गाय कैबिनेट में गौ-फिनाइल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इस आदेश के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गौ-फिनायल की आड़ में किसी एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस की मांग की कि अगर सरकार को गौ-फिनायल का इस्तेमाल करना ही है तो कमलनाथ सरकार के समय जो गौशालाएं बनाई गई हैं उन्हें गौ-फिनायल के प्रॉडक्शन का ठेका दिया जाए। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मंत्री और प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से 15 महीने में भ्रष्टाचार की गंदगी सरकारी दफ्तरों में फैलाई थी, उसको साफ करने के लिए और कांग्रेस की मानसिकता को दुरुस्त करने के लिए गौ-फिनायल से सफाई बहुत आवश्यक है।

गौमूत्र से गौ-फिनायल

गाय के मूत्र एक असरदार कीटाणुनाशक माना जाता रहा है। इससे फिनायल बनाने की पहल कुछ स्थानों पर शुरू हुई है। गौमूत्र में पाइन ऑयल, पानी, सिट्रोनेला और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ मिलाकर एक मशीन में मिक्स किया जाता है। 100 लीटर फिनायल बनाने के लिए करीब 70 लीटर गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। गौमूत्र से एक लीटर फिनायल बनाने में 25 रुपए का खर्च आता है। बाजार में इसकी कीमत 30 रुपए प्रति लीटर है। पतंजलि गौमूत्र से बना फिनायल बेच रही है। कई अन्य छोटी कंपनियां गोमूत्र फिनायल का प्रॉडक्शन कर रही हैं।

कृषि में गौमूत्र का प्रयोग

वर्तमान मानव जीवन कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों को झेल रहा है। रासायनिक खादों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में गौमूत्र एवं अन्य अपशिष्ट वैकल्पिक खाद और कीटनाशक के रूप में सामने आ रहे हैं।

गौमूत्र के औषधीय प्रयोग

हजारों वर्ष पहले लिखे गए आयुर्वेद में गौमूत्र को अमृत सदृश माना गया है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी गौमूत्र को जैविक औषधीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

गृह सफाई में प्रयोग

हिंदुओं की प्राचीन परंपरा के लिहाज से गौमूत्र एक पवित्र एवं उपयोगी द्रव है। गौमूत्र को अब फिनायल की जगह प्रयोग करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इनका कहना है

अभी उपयोग में लाए जा रहे फिनाइल रासायनिक तौर पर पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। गौमूत्र से बना फिनायल पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है। मैंने इसके लिए पहले भी पहल की थी। सभी सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग अनिवार्य होना चाहिए। इससे गौ-संरक्षण के अभियान को भी बढ़ा मिलेगा।

मेनका गांधी, सांसद, भाजपा

सभी सरकारी कार्यालयों व परिसर को साफ करने के लिए रासायनिक रूप से निर्मित फिनाइल को गौमूत्र फिनाइल से बदलना होगा। आदेश में पंचायतों से लेकर मंत्रालय स्तर तक के सरकारी दफ्तरों में गौ-फिनायल का इस्तेमाल करने की बात कही गई है।

श्रीनिवास शर्मा, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

गौमूत्र के बॉटलिंग प्लांट और गौमूत्र के कारखानों को स्थापित करने को बढ़ावा देने लिए यह निर्णय लिया गया है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में गायों के लिए कुछ कर तो नहीं सकी, लेकिन गौमाता को लेकर राजनीति करने में लगी हुई है। हमारी सरकार में अब गाय सड़कों पर नहीं दिखती हैं।

प्रेम सिंह पटेल, मंत्री, पशुपालन विभाग

मुख्यमंत्री गौसेवा योजना संचालित गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। गौशालाओं व गौ-अभ्यारण्य केंद्रों में निर्मित गौ–फिनाइल का उपयोग शासकीय कार्यालयों में किया जाएगा। गौ-शालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह योजना कारगर साबित होगी। जबलपुर में गौमूत्र से विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है।

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर, जबलपुर

सरकार पतंजलि को लाभ पहुंचाने के लिए यह आदेश लेकर आई है। गौ-फिनायल की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सरकार को गौ-फिनायल का इस्तेमाल करना ही है तो कांग्रेस सरकार के समय जो गौशालाएं बनाई गई हैं उन्हें गौ-फिनायल बनाने का ठेका दिया जाए।

कुणाल चौधरी, विधायक, कांग्रेस

■ आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की भी व्यवस्था ■ चारा-भूसा के लिए 29 करोड़ 85 लाख हो चुका जारी

गौशालाओं को प्रति गाय 20 रुपए दे रही सरकार

संवाददाता, भोपाल

शिवराज सरकार सड़कों पर आवार घूमने वाली गायों की दुर्दशा को रोकने के लिए प्रयासरत है। इसी के चलते खासकर गायों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर पूरा फोकस कर रही है। सरकार के प्रयास का असर भी अब दिखने लगा है। पहले गांवों में लोग गायों को आवारा छोड़ देते थे, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद अब लोग गायों को नहीं छोड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में गौशालाओं को प्रतिदिन 20 रूपए प्रति गौ-वंश के मान से ही राशि प्रदाय की जा रही है। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का आदेश यथावत है। अप्रैल 2020 में प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश के चारे-भूसे के लिए 29 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

इसके अलावा 28 करोड़ की राशि और जारी की जा चुकी है। गौशालाओं के गौवंश के चारा-भूसा अनुदान के लिए सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान के अतिरिक्त भी यदि राशि की आवश्यकता होती है तो शासन द्वारा व्यवस्था की जाती है। बोर्ड के अनुसार मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत नवीन 1000 गौशालाओं के लिए 2 माह का चारा-भूसा अनुदान राशि 11 करोड़ 68 लाख कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समितियों को पहले ही प्रदाय कर दी गई थी ताकि जिला प्रशासन को गौशाला संचालन प्रारंभ करवाने में कठिनाई न हो। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 700 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

गौशाला विकास के लिए कामधेनु

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश के 52 हजार गांवों में गौशालाओं के विकास के लिए कामधेनु योजना बनाई गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आजीविका के अतिरिक्त संसाधन विकसित होंगे वहीं जॉबकार्डधारी अकुशल श्रमिकों को व्यापक पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। कामधेनु योजना के तहत गांवों में स्थित गौशालाओं का विकास किया जा रहा है। इसमें गौशालाओं तक पहुंच मार्गों का निर्माण करने के साथ ही पशु अवरोधक खंती, पेयजल व्यवस्था के लिए कुंओं का निर्माण या छोटा तालाब, गौशाला की भूमि पर पौधरोपण, चारागाह का विकास तथा गोबर की खाद तैयार करने के लिए खंती का निर्माण कराया गया है। गौशाला में विकास की क्या-क्या आवश्यकता है इसका चिन्हांकन सरपंच, सचिव, पटवारी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, उपयंत्री एवं गौशाला के प्रबंधक द्वारा सामूहिक रूप से सर्वे किया जाता है। इसके बाद स्वीकृत कार्यों के आधार पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मनरेगा के तहत यह कार्य कराए गए हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
रायसेन, बृजेश ठाकुर-9926777555
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
गंजबासौदा, प्रदीप श्रीवास्तव- 7987780456
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति -9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)